नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 072
दि. 14.12.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

केरल की राजनीति में भूचाल, तिरुवनंतपुरम में बदला सत्ता का गणित

केरल के स्थानीय निकाय चुनावों ने राज्य की राजनीति में ऐसा मोड़ ला दिया है, जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक मुश्किल मानी जा रही थी। दशकों से वामपंथ का मजबूत किला कहे जाने वाले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सत्ता समीकरणों को पूरी तरह उलट दिया है। 101 वार्डों वाले इस नगर निगम में बीजेपी ने 50 वार्ड जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हुए यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब केरल की राजनीति में वह केवल हाशिए की ताकत नहीं रही। पिछले 45 वर्षों से सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले एलडीएफ के कब्जे में रहा यह नगर निगम पहली बार ऐसी स्थिति में पहुंचा है, जहां वामपंथ निर्णायक भूमिका में नजर नहीं आ रहा।

चुनाव नतीजों में एलडीएफ को जहां 29 वार्डों पर संतोष करना पड़ा, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ केवल 19 वार्डों तक सिमट गया। दो निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत के बावजूद तस्वीर साफ है कि बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में एक नया राजनीतिक इतिहास रच दिया है। यह जीत इसलिए भी ज्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि तिरुवनंतपुरम को कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ माना जाता रहा है। थरूर की पहचान एक प्रभावशाली नेता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित चेहरा रही है, लेकिन उनके ही क्षेत्र में कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन पार्टी के लिए गंभीर आत्ममंथन का विषय बन गया है।

तिरुवनंतपुरम के अलावा राज्य की अन्य नगरपालिकाओं में भी एनडीए के बढ़ते प्रभाव के संकेत साफ दिखाई दिए। पलक्कड नगरपालिका में बीजेपी ने कड़े मुकाबले में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को हराकर अपना कब्जा बरकरार रखा। वहीं तिरुपुनुत्थापुरा नगरपालिका सीट भी एनडीए ने यूडीएफ से छीन ली। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भले ही बीजेपी निर्णायक बहुमत से एक सीट पीछे रह गई हो, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में उसका उभरना

वामपंथ और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। त्रिशूर जिले में भी बीजेपी की मौजूदगी पहले से अधिक मजबूत होती दिखी। अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी की लोकसभा जीत के बाद इस जिले में पार्टी की गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। कोडुंगल्लूर नगरपालिका में बीजेपी ने 46 में से 18 वार्ड जीतकर मजबूत आधार तैयार किया। त्रिशूर नगर निगम में पार्टी ने 8 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि गुरुवयूर और वडक्कनचेरी नगरपालिकाओं में दो-दो वार्डों पर कब्जा जमाया। कुन्नमकुलम में 7, इरिंजलाकुडा में 6 और चलाकुडी नगरपालिका में एक वार्ड जीतकर बीजेपी ने यह संदेश दिया कि शहरी इलाकों में उसका जनाधार लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही पार्टी ने ब्लॉक पंचायतों में 4 और ग्राम पंचायतों में 167 वार्ड जीतकर जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया है।

राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार दोपहर 2.30 बजे तक भाजपा नेतृत्व वाले मोर्चे ने केरल में कुल 1,085 ग्राम पंचायत वार्ड और 44 ब्लॉक पंचायत वार्डों में जीत दर्ज की। इन सफलताओं में कोल्लम, कोझिकोड, कन्नूर और कोच्चि जैसे बड़े नगर निगमों के वार्ड भी शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में एलडीएफ के कार्यकाल के दौरान सामने आए कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असंतोष को लेकर बीजेपी ने जिस आक्रामक अभियान को चलाया, उसने मतदाताओं को प्रभावित किया और पार्टी को अप्रत्याशित बढ़त दिलाई। यही वजह है कि इन नतीजों को अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

तिरुवनंतपुरम नगर निगम में एनडीए की इस सफलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से केरल की जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह परिणाम इस बात का प्रमाण है कि लोगों को भरोसा है कि राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही पूरा कर सकता है। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए इसे केरल की राजनीति में नए युग की शुरुआत बताया।

दूसरी ओर, इन नतीजों ने कांग्रेस के भीतर भी बेचैनी बढ़ा दी है। शशि थरूर के लोकसभा क्षेत्र में पार्टी की हार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहले से ही पार्टी लाइन से अलग राय रखने, प्रधानमंत्री मोदी के कुछ कदमों की सराहना करने और राहुल गांधी की बैठकों से दूरी बनाए रखने को लेकर थरूर पर नजरें टिकी हुई थीं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव में मिली इस हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व उनके खिलाफ सख्त रुख अपना सकता है। हालांकि यह भी चर्चा है कि यदि पार्टी उनके खिलाफ कोई कदम उठाती है, तो थरूर इसे अपने राजनीतिक भविष्य के लिए एक नए रास्ते के रूप में देख सकते हैं।

कुल मिलाकर तिरुवनंतपुरम नगर निगम के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि केरल की राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही। दशकों से मजबूत माने जा रहे वामपंथी किले में सेंध लगाकर बीजेपी ने राज्य की राजनीति में नई बहस और नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। आने वाले विधानसभा चुनावों में यह बदलाव किस दिशा में जाएगा, यह देखना अब पूरे देश के लिए दिलचस्प होगा।

फर्जी ट्रेडिंग के जाल में करोड़ों की ठगी, अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा

देश में ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को ठगने वाले साइबर अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था। शुरुआती जांच में करीब पांच करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है, जिससे इस साइबर रैकेट के बड़े और संगठित होने के संकेत मिले हैं।

इस मामले में पुलिस ने देश के चार अलग-अलग राज्यों से कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें तीन आरोपी दिल्ली, तीन राजस्थान, दो महाराष्ट्र और एक बेंगलुरु का रहने वाला है। सभी आरोपियों को अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई के दौरान दबोचा गया। पुलिस का मानना है कि यह गिरोह केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं। इसी दिशा में अब पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों, उनके वित्तीय लेन-देन और विदेशी कड़ियों की गहन जांच कर

रही है।

आईएफएसओ यूनिट के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में महाराष्ट्र निवासी सुल्तान सलीम शेख और सतीश कुमार, बेंगलुरु निवासी सैयद अहमद चौधरी, दिल्ली के तुषार मलिया, शिवम और सुनील, तथा राजस्थान के परभू दयाल, तरुण शर्मा और सुरेश कुमार कुमावत शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन, कई आपत्तिजनक चैट, चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और बेंगलुरु पुलिस का एक नोटिस भी बरामद किया है। इन डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साफ हुआ है कि गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि यह ठगी का नेटवर्क दिल्ली के द्वारका इलाके के एक होटल से संचालित किया जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल के कमरों से साइबर ठगी का पूरा खेल चल रहा है और कई बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम को इधर-उधर किया जा रहा है। सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने होटल से चार आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं।

होटल से पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे एक अन्य संदिग्ध के निर्देश पर काम कर रहे थे और साइबर ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलते रहते थे और अलग-अलग शहरों से नेटवर्क को संचालित करते थे। आरोपी सुल्तान सलीम शेख ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने एक संदिग्ध के कहने पर एक्सिस बैंक में चालू खाता खुलवाया था। उसे भरोसा दिलाया गया था कि ठगी के जरिए होने वाले लेन-देन पर उसे 25 प्रतिशत कमीशन मिलेगा। लालच के तौर पर उसे एक नया मोबाइल फोन भी दिया गया था। पुलिस ने उसके मोबाइल से कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन अलर्ट बरामद किए हैं।

पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि यह गिरोह बैंक खाताधारकों, बिचौलियों और साइबर ठगी के मुख्य सरगनाओं के संगठित नेटवर्क के जरिए काम करता था। बिचौलिए लोगों को आसानी से पैसे कमाने का लालच देकर उनके बैंक खाते हासिल करते थे और फिर कमीशन के बदले उन खातों को साइबर ठगों को सौंप देते थे। कुछ लोग तय वेतन पर काम कर रहे थे, जबकि कुछ पूरी तरह कमीशन मॉडल पर जुड़े हुए थे। इस तरह का नेटवर्क साइबर अपराध को और ज्यादा जटिल और खतरनाक बना देता है।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि ठगी की कुल रकम कितनी है, पीड़ितों की संख्या कितनी है और इस पूरे रैकेट के पीछे कौन-कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं। यह मामला एक बार फिर यह चेतावनी देता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर फैल रहे फर्जी प्लेटफॉर्म से सावधान रहना कितना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चूक लोगों की जीवन भर की कमाई को पल भर में खत्म कर सकती है।

नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार, 92 करोड़ की जब्ती से हिली उग्रवादी अर्थव्यवस्था

देश को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ी और निर्णायक सफलता हासिल की है। विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के समन्वित अभियान के तहत नक्सलियों और उनसे जुड़े नेटवर्क की करीब 92 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। शनिवार को जारी सरकारी बयान में कहा गया कि इस कार्रवाई से न केवल नक्सली संगठनों की आर्थिक कमर टूटी है, बल्कि अर्बन नक्सलियों को भी गहरा नैतिक और मनोवैज्ञानिक झटका लगा है। सरकार का मानना है कि इस कदम से नक्सलियों के सूचना तंत्र और फंडिंग नेटवर्क पर कड़ा नियंत्रण स्थापित हुआ है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सल-मुक्त बनाने का उसका लक्ष्य अडिग है और इसी दिशा में संस्थागत स्तर पर भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए में एक समर्पित प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जो विशेष रूप से नक्सलवाद से जुड़े मामलों की जांच और कार्रवाई पर केंद्रित है। इस प्रकोष्ठ ने अब तक करीब 40 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय प्राधिकारियों ने लगभग 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्ति जब्त की है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में 12 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई केवल हथियारबंद नक्सलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके शहरी सहयोगियों और वैचारिक समर्थन देने वालों तक भी पहुंच रही है।

केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ जारी सुरक्षा अभियानों की उपलब्धियों का भी विस्तार से उल्लेख किया है। बयान के अनुसार, वर्ष 2014 में देश के 36 जिले ऐसे थे, जो नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित माने जाते थे। लगातार और सख्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 तक यह संख्या घटकर मात्र तीन जिलों तक सिमट गई है। यह आंकड़ा सरकार की उस रणनीति को मजबूत करता है, जिसमें सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ-साथ विकास और आत्मसमर्पण नीति को भी समान महत्व दिया गया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में अब तक सुरक्षा बलों ने 317 नक्सलियों को मुठभेड़ों में ढेर किया है। इसके अलावा 862 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 1,973 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। सरकार का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें पुनर्वास देने की नीति भी इस सफलता का अहम हिस्सा है।

सुरक्षा बलों की हालिया बड़ी कामयाबियों में 'ब्लैक फॉरेस्ट' अभियान का विशेष उल्लेख किया गया है। इस अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने 27 कट्टर नक्सलियों को मार गिराया, जिन्हें संगठन के भीतर बेहद खतरनाक और रणनीतिक माना जाता था। सरकार का कहना है कि इस तरह के लक्षित अभियानों से नक्सली नेतृत्व कमजोर हुआ है और उनके संगठनात्मक ढांचे में भारी दरार पड़ी है।

कुल मिलाकर केंद्र सरकार का दावा है कि आर्थिक कार्रवाई, खुफिया तंत्र की मजबूती और सुरक्षा बलों के सटीक अभियानों के कारण नक्सलवाद अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 92 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्ती को सरकार नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे प्रभावी आर्थिक चोट मान रही है। आने वाले महीनों में इस तरह की कार्रवाइयों को और तेज करने की तैयारी है, ताकि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह इतिहास बनाया जा सके।

6 जनवरी को बदलेगा कर्नाटक का नेतृत्व? डीके शिवकुमार को लेकर कांग्रेस विधायक के दावे से फिर गरमाई राजनीति

कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और सत्ता के शीर्ष पर बदलाव की अटकलों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के शांत पड़ते ही अब नया बयान सामने आ गया है, जिसने कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों जगह हलचल मचा दी है। रामनगरा से कांग्रेस विधायक एचए इकबाल हुसैन ने दावा किया है कि आगामी 6 जनवरी को डीके शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं और कयासों का दौर शुरू हो गया है।

दरअसल, पिछले कई दिनों से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को लेकर अंदरूनी खींचतान की खबरें सामने आ रही थीं। कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले तय किए गए ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री फॉर्मूले को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष है और सिद्दरमैया तथा डीके शिवकुमार के समर्थकों के बीच खामोश संघर्ष चल रहा है। हालात उस समय और चर्चा में आ गए थे जब यह संकेत मिलने लगे कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने डीके शिवकुमार को ब्रेकफास्ट पर आमंत्रित किया और कांग्रेस आलाकमान ने भी दोनों नेताओं को आपसी मतभेद सुलझाने के निर्देश दिए, जिसके बाद यह माना गया कि मामला फिलहाल शांत हो गया है।

लेकिन अब कांग्रेस विधायक एचए इकबाल हुसैन के बयान ने इस शांति को फिर से तोड़ दिया है। शनिवार को उन्होंने आशंका जताई कि मुख्यमंत्री सिद्दरमैया अपने पद से हट सकते हैं और इसके बाद डीके शिवकुमार को राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि 99 प्रतिशत संभावना है कि शिवकुमार 6 जनवरी को मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इकबाल हुसैन को डीके शिवकुमार का कट्टर समर्थक माना जाता है और उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जाता।

जब उनसे 6 जनवरी की तारीख के पीछे के कारण के बारे में पूछा गया तो इकबाल हुसैन ने साफ कहा कि यह तारीख कैसे तय हुई, इसकी उन्हें खुद पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी और राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा चल रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर 6 जनवरी को नहीं तो 9 जनवरी को डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। इससे पहले भी इकबाल हुसैन सार्वजनिक रूप से डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर चुके हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर एक धड़ा खुलकर सामने आ चुका है।

इस बयान के बाद कर्नाटक कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि इस तरह के दावे सियासी दबाव बढ़ाने और नेतृत्व परिवर्तन की बहस को फिर से जिंदा करने का काम कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये दावे महज राजनीतिक बयानबाजी हैं या फिर कर्नाटक की सत्ता में सचमुच कोई बड़ा बदलाव होने वाला है।

कच्छ में धरती की हलचल, एक बार फिर महसूस हुए भूकंप के झटके

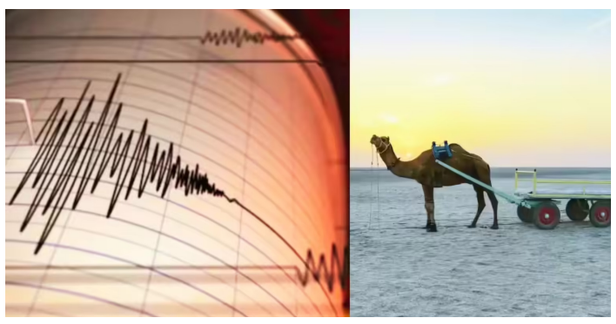

गुजरात के कच्छ जिले में शनिवार को एक बार फिर धरती हिलने से लोगों में हल्की दहशत फैल गई, जब दोपहर बाद 3.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, भूकंप का यह झटका दोपहर 2 बजकर 47 मिनट पर दर्ज किया गया। इसका केंद्र कच्छ जिले के गढ़शीशा क्षेत्र से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित था। झटके इतने हल्के थे कि कुछ सेकंड में ही समाप्त हो गए, लेकिन कई इलाकों में लोगों ने कंपन को साफ तौर पर महसूस किया।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने राहत की बात बताते हुए कहा कि भूकंप से किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। न तो किसी इमारत को क्षति पहुंची है और न ही किसी के घायल होने की खबर सामने आई है। इसके बावजूद भूकंप के झटकों के बाद कुछ समय के लिए लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए और एक-दूसरे से जानकारी लेते नजर आए।

गांधीनगर स्थित आईएसआर के अनुसार, कच्छ क्षेत्र में इस महीने यह पांचवां मौका है जब रिक्टर पैमाने पर तीन से अधिक तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को जिले में 3.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था, जबकि बुधवार को 3.7 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे। लगातार आ रहे इन झटकों ने एक बार फिर कच्छ के भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र होने की याद दिला दी है।

विशेषज्ञों के अनुसार कच्छ इलाका भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है और यहां समय-समय पर हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। हालांकि शनिवार को आए भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं रही, लेकिन लगातार बढ़ती भूकंपीय गतिविधियों पर वैज्ञानिक और प्रशासनिक एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहें। साथ ही भूकंप के दौरान और उसके बाद अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है। फिलहाल कच्छ में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन बार-बार आ रहे झटकों ने क्षेत्र में सतर्कता जरूर बढ़ा दी है।

संपादकीय

निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर सुप्रीम राय

देश में लंबे समय से यह मुद्दा सार्वजनिक विमर्श में रहा है कि विषम परिस्थितियों में एक त्रासदी से मुक्ति हेतु इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए या नहीं। समय-समय पर अदालती फैसलों ने मार्गदर्शक भूमिका निभाई है। साथ ही कोशिश की गई है कि इस छूट का दुरुपयोग न किया जा सके। हाल ही में एक ज्वलंत प्रसंग पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी थी कि हमें अब कुछ करना होगा, इस तरह के त्रासद जीवन की कोई तार्किकता नहीं है। दरअसल, यह मामला एक 32 वर्षीय युवक का है, जो पिछले 13 सालों से कोमा जैसी स्थिति में है। यह अब केवल महज चिकित्सीय त्रासदी का मामला नहीं रह गया है। अब यह एक महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक प्रश्न भी बन चुका है। निश्चित रूप से शीर्ष अदालत की टिप्पणी देश में जीवन के अंतिम क्षणों में गरिमापूर्ण व्यवहार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। निश्चय ही यह प्रसंग अतीत में बहुचर्चित अरुणा शानबाग के मामले की यादें फिर से ताजा कर देता है। इस प्रसंग ने ही देश को पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु के प्रश्न का सामना करने के लिये बाध्य किया था। वर्ष 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के मामले में फैसला सुनाते हुए, सैद्धांतिक रूप से निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी। दरअसल, अरुणा शानबाग एक भयानक हमले के बाद से ही 42 वर्षों से कोमा जैसी स्थिति में रही थीं। भले ही अदालत ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, लेकिन साथ ही उसके साथ कुछ प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपायों के अनुपालन के भी निर्देश दिए थे। निश्चित रूप से इस मामले में अदालती फैसला नैतिक प्रेरणा का स्रोत भी बना। कालांतर में जिसके चलते वर्ष 2018 में एक संविधान पीठ ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की। साथ ही इसके लिये एक आवश्यक प्रक्रिया भी निर्धारित की थी। जिसका मकसद था कि समाज में कहीं इस छूट का दुरुपयोग आपराधिक स्वार्थों के लिये न किया जा सके।

वर्ष 2023 में, अदालत ने इन दिशानिर्देशों को और सरल बनाने का प्रयास किया। जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि प्राथमिक और माध्यमिक चिकित्सा बोर्डों द्वारा स्थिति के मूल्यांकन की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल देश में वही प्रक्रिया आज भी चल रही है। बहरहाल, वर्तमान मामले में बार-बार की गई अपीलें, इससे जुड़ी खामियों को भी उजागर करती हैं। दरअसल, ऐसे मामलों में पीड़ित को घर में दी जाने वाली देखभाल अपर्याप्त ही साबित होती है। वहीं दूसरी ओर राज्य का समर्थन भी पर्याप्त नहीं रहा है। इसके अलावा ऐसे मामलों से जुड़ी अनसुलझी नैतिक दुविधाएं असमंजस की स्थिति पैदा करती रही हैं। निस्संदेह, इस मामले में किसी युवा वयस्क के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की पहली स्पष्ट स्वीकृति हो सकती है। आज देश में हजारों मरीज कोमा जैसी अवस्था में नारकीय जीवन जी रहे हैं। जो उनके परिवारों के लिये भी एक त्रासदी की स्थिति है। जहां परिवार एक ओर भावनात्मक संकट से जूझ रहे होते हैं, वहीं रोगी के उपचार से जनित आर्थिक बोझ भी निरंतर बढ़ता जाता है। दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर भी सवाल उठते रहे हैं। निस्संदेह, अदालत को जटिल परिस्थितियों में जैविक अस्तित्व के कठोर विस्तार के बजाय रोगी की मुक्ति और परिवार की पीड़ा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे में यदि एम्स 17 दिसंबर तक मामले में जीवन की निरर्थकता की पुष्टि करता है, तो निष्क्रिय इच्छामृत्यु की स्वीकृति एक मिसाल कायम कर सकती है। इसके बाद दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों को भी स्पष्ट किया जा सकेगा। साथ ही जीवन के अंतिम विकल्पों का सम्मान किया जा सकेगा। देश के नीति-नियंताओं को कोमा जैसी अवस्था में सालों जूझते लोगों के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने चाहिए, जिससे ऐसे रोगियों की उपचारात्मक देखभाल और परामर्श को एकीकृत किया जा सके। मानवीय करुणा की मांग है कि जीवन की पवित्रता और पीड़ा की क्रूरता के बीच संतुलन बनाया जाए। इच्छामृत्यु जब सहमति से होगी तो मानवता को कायम रखा जा सकता है। न्यायपालिका को ऐसा न्याय देना चाहिए, जो रोगी को पीड़ा से मुक्त करे और एक करुणामय भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे।

आम उपभोक्ता को मिले घटी ब्याज दरों का लाभ

> यदि आम आदमी को सस्ते कर्ज का लाभ मिलेगा, तो ईएमआई में कमी आएगी और ऋण लेने वालों को फायदा होगा। इससे घरों और वाहनों की मांग बढ़ेगी और रियल स्टेट उद्योग को ब्याज दरों में कटौती से राहत मिलेगी।

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा हाल में ब्याज दरों में कटौती के मद्देनजर रेपो रेट में 25 आधार अंकों की जो कटौती की गई है, उसका लाभ बैंकों द्वारा विभिन्न वर्ग के ग्राहकों तक पहुंचाया जाना जरूरी है।

हाल ही में आरबीआई द्वारा आयोजित मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट को घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया गया है। इस फैसले के पीछे प्रमुख कारण देश में महंगाई का कम होना और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.3 प्रतिशत होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी को दूर करने और इसकी पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की योजना बना रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर घटाने का प्रमुख कारण महंगाई पर नियंत्रण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2025 में खुदरा महंगाई पिछले 10 साल के न्यूनतम 0.25 प्रतिशत पर और थोक महंगाई 27 महीने के निचले स्तर 1.21 प्रतिशत से नीचे आ गई। महंगाई में यह कमी मुख्यतः सब्जियां, फल, अंडे, फुटवियर, अनाज और उससे बने उत्पाद, बिजली, परिवहन और संचार जैसी वस्तुओं के दामों में गिरावट के कारण हुई है। इसके अलावा, हालिया जीएसटी सुधारों ने भी महंगाई नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर, 2025 में शाकाहारी थाली की कीमत 27.8 रुपये और मांसाहारी थाली की कीमत 54.4 रुपये रही। विभिन्न शोध रिपोर्टों में, बेहतर खाद्यान्न उत्पादन और अच्छे मानसून के कारण कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को मिल रही अनुकूलताओं के चलते आगामी महीनों में महंगाई और कम हो

सकती है।

भारत के विकास पर कई रिपोर्टों में कहा गया है कि टैक्स व महंगाई घटने से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और भारत की क्रेडिट रेटिंग सुधर रही है, लेकिन तेज विकास के मद्देनजर कर्ज सस्ता किए जाने की जरूरत लगातार बनी हुई है।

रेटिंग एजेंसियों के अनुसार सरकार के बड़े फैसलों से उपभोग आधारित बढ़ोतरी को बढ़ावा मिलेगा। 'जीएसटी की कम दरें मध्यम वर्ग के उपभोग को बढ़ावा देंगी और इस वर्ष शुरू की गई आयकर कटौती एवं ब्याज दरों में कटौती का पूरक बनेंगी। इन बदलावों से चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में निवेश की तुलना में उपभोग वृद्धि का एक बड़ा चालक बन सकता है।' उल्लेखनीय है कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की मध्यवर्ती आर्थिक समीक्षा में कहा कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाए जाने और महंगाई में कमी का लाभ भारत की अर्थव्यवस्था को मिला है। लेकिन अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक आर्थिक मुश्किलों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था का अपनी क्षमता के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उद्योगों और व्यापार को आर्थिक और वित्तीय सहारा जरूरी है।

विश्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत विकास की डगर पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब भारत को 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए आर्थिक-वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को और तेजी देने तथा उद्योग-कारोबार के लिए आसान ब्याज दरों पर कर्ज जुटाकर निजी पूंजी जुटाने को बढ़ावा देने की जरूरत बताई गई है।

अब ब्याज दर घटाए जाने के कारण सस्ते कर्ज से आर्थिक गतिविधियों में तेजी की संभावना विकास दर को बढ़ाने के लिए सकारात्मक संदेश है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति को मजबूत बनाने, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को व्यापक आर्थिक विवेक से प्रबंधित करने, उद्यमियों को नीतिगत स्थिरता, नवाचार एवं वृहद आर्थिक नीति उपलब्ध कराने के मद्देनजर सस्ता कर्ज लाभप्रद होगा। सस्ते कर्ज के कारण विदेशी निवेश भी बढ़ेंगे।

ग्रामीण और शहरी मांग में सुधार, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के विकास को प्रोत्साहित करेगा। सस्ते कर्ज के चलते स्थानीय और घरेलू बाजार तेजी से बढ़ेंगे और बैंक व वित्तीय संस्थाओं की स्थिरता बनी रहेगी। यदि आम आदमी को सस्ते कर्ज का लाभ मिलेगा, तो ईएमआई में कमी आएगी और ऋण लेने वालों को फायदा होगा। इससे घरों और वाहनों की मांग बढ़ेगी और रियल स्टेट उद्योग को ब्याज दरों में कटौती से राहत मिलेगी, खासकर मकानों की बिक्री में आई गिरावट के बाद। उम्मीद करें कि घटी हुई ब्याज दर से सभी वर्ग के बैंक ग्राहक लाभान्वित होंगे।

प्रेरणा

एक टूटे फूलदान की कीमत और इंसानी

प्राचीन जापान के इतिहास में एक ऐसा सम्राट हुआ करता था, जिसकी विलासिता और वैभव की चर्चा दूर-दूर तक थी, पर उससे भी अधिक चर्चा उसके सनकी स्वभाव और निर्दय निर्णयों की होती थी। उसके लिए इंसानी भावनाएँ और परिस्थितियाँ कोई मायने नहीं रखती थीं। छोटी-सी भूल पर भी वह ऐसा कठोर दंड देता कि लोग थर्रा उठते। दरबार में कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करता था, क्योंकि सभी जानते थे कि सम्राट की नाराज़गी जीवन और मृत्यु का कारण बन सकती है।

उस सम्राट के महल में बीस अत्यंत दुर्लभ और सुंदर फूलदानों का संग्रह था। वे फूलदान केवल सजावट की वस्तु नहीं थे, बल्कि सम्राट के अहंकार और घमंड के प्रतीक थे। वह अकसर दरबारियों और मेहमानों को उन्हें दिखाकर गर्व से भर जाता और कहता कि यह संग्रह उसकी महानता का प्रमाण है। उन फूलदानों की देखभाल में कई सेवक लगाए गए थे, जिन्हें हर समय भय रहता था कि कहीं उनसे कोई चूक न हो जाए।

एक दिन महल में फूलदानों की सफाई हो रही थी। सभी सेवक अत्यंत सावधानी से अपना काम कर रहे थे, फिर भी दुर्भाग्यवश एक सेवक के हाथ काँप गए और एक फूलदानी नीचे गिरकर टूट गई। जैसे ही यह खबर सम्राट

तक पहुँची, उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने बिना किसी जांच या सहानुभूति के तुरंत आदेश दे दिया कि उस सेवक को फांसी पर लटका दिया जाए। दरबार में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने हाथ जोड़कर दया की भीख माँगी, यह कहा कि यह एक दुर्घटना थी, जानबूझकर किया गया अपराध नहीं, लेकिन सम्राट का मन नहीं पसीजा।

उसी समय दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसके वस्त्र साधारण थे, पर चेहरे पर अद्भुत तेज और आत्मविश्वास था। उसने शांत स्वर में कहा कि वह टूटी हुई फूलदानी को जोड़ने में निपुण है और उसे इस तरह ठीक कर सकता है कि वह पहले जैसी ही दिखाई दे। सम्राट को यह बात पसंद आई। उसने सोचा कि यदि फूलदानी फिर से वैसी ही बन गई तो उसका संग्रह अधूरा नहीं रहेगा। उसने वृद्ध को अपनी बाकी उन्नीस फूलदानियाँ दिखाईं और कहा कि यदि वह टूटी हुई फूलदानी को भी इन्हीं के समान बना देगा तो उसे जो चाहे इनाम मिलेगा।

सम्राट की बात समाप्त होते ही अचानक वह वृद्ध अपनी लाठी के सहारे आगे बढ़ा और देखते ही देखते एक-एक कर सभी उन्नीस फूलदानियाँ तोड़ दीं। पूरा दरबार सन्न रह गया। सम्राट क्रोध से लाल हो उठा और चिल्लाकर बोला कि यह कैसी मूर्खता है, उसने ऐसा क्यों किया। तब उस वृद्ध ने अत्यंत दृढ़ता और शांति के साथ कहा कि वह जानता था कि हर फूलदानी के पीछे किसी न किसी निर्दोष की जान जाने वाली है। उसने यह भी कहा कि वह केवल एक कारीगर नहीं, बल्कि एक इंसान है, और इंसान होने के नाते उसका धर्म है कि वह जीवन की रक्षा करे। आज उसने उन्नीस फूलदान नहीं तोड़े, बल्कि उन्नीस लोगों की जान बचाई है। अब सम्राट चाहे तो उसे फांसी दे सकता है।

वृद्ध की इन बातों ने सम्राट के हृदय में तूफान खड़ा कर दिया। पहली बार उसे अपनी क्रूरता का वास्तविक रूप दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सनक और अहंकार के कारण कितने निर्दोष लोग भय में जीते हैं और कितनी ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ जाती हैं। उस क्षण उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने न केवल उस सेवक को, बल्कि उस साहसी वृद्ध को भी क्षमा कर दिया।

उस दिन महल में कोई फूलदानी नहीं बची, लेकिन सम्राट के भीतर एक नया विचार जन्म ले चुका था। उसे समझ आ गया था कि पत्थर और मिट्टी से बनी वस्तुएँ चाहे कितनी भी कीमती क्यों न हों, उनका मूल्य कभी भी एक इंसानी जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। यही घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई, जिसने यह सिखाया कि सच्ची समझदारी शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि करुणा, विवेक और मानवता की रक्षा में होती है।

आतंक से मुक्त माओवादियों का गढ़, विकास, शांति और विश्वास की दिख रही रोशनी

देश अब माओवाद से मुक्त हो रहा है। मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों की प्रभावकारी कार्रवाइयों की वजह से यह स्थिति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व ने देश को माओवादी आतंक से मुकाबले के निर्णायक दौर तक पहुंचाने की दिशा दिखाई है।

ऑएक ओर राज्य पुलिस बल के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कदमताल करते हुए माओवादियों के गढ़ में हुंकार भर रहे हैं, माओवादियों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर रहे हैं तो दूसरी ओर सरकार की योजनाओं का पूरा जोर इन क्षेत्रों के विकास और स्थानीय लोगों के पुनरुत्थान पर केंद्रित है। नतीजन जिस लाल गलियारे में कभी हिंसा और असुरक्षा का साया मंडराता था, वहां आज विकास, शांति और विश्वास की रोशनी दमक रही है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 22 महीनों में सुरक्षा बलों ने 487 से अधिक माओवादियों को मार गिराया है, 2240 ने आत्मसमर्पण किया है और 1833 गिरफ्तार किए गए हैं। यह सफलता अपने आप में रिकार्ड है। जिन इलाकों में कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां स्कूल, सड़कें, अस्पताल और मोबाइल टावर खड़े हैं। हाल में सेंट्रल कमेटी के बड़े माओवादी नेताओं-सुधाकर, बसवराजू और हिडमा के मारे जाने से छत्तीसगढ़ और इसकी सीमा से लगे अन्य राज्यों में माओवाद का ढांचा पूरी तरह हिल गया है। बीजापुर का करेंगुड़ा आपरेशन इस बदलाव का प्रतीक बन चुका है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित माओवादियों एवं माओवाद प्रभावित लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए देश की सबसे आकर्षक पुनर्वास नीति लागू की है। पुनर्वास ही नहीं, राज्य सरकार की तरफ से आत्मसमर्पित माओवादियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की भी इस लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके तहत सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को तीन वर्षों तक 10,000 रुपये मासिक सहायता की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों में आवासीय प्लाट और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का प्रविधान किया गया है। सरकार की नीति में यह बड़ा सकारात्मक बदलाव है कि पहले सुरक्षा बलों को मिलने वाला इनाम अब आत्मसमर्पण करने वालों को दिया जा रहा है। और तो और, 80 प्रतिशत से अधिक सदस्यों के सामूहिक आत्मसमर्पण पर दोगुना इनाम घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सरेंडर नीति में बदलाव करते हुए वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप माओवादियों के आत्मसमर्पण में तेजी आई है।

15,000 प्रधानमंत्री आवास आत्मसमर्पित माओवादियों एवं माओवाद पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए निर्माणाधीन हैं। दूरस्थ गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल कनेक्टिविटी और आधारभूत सेवाएं पहले की अपेक्षा अब तेजी से पहुंच रही हैं। 403 गांवों में 81,090 आधार कार्ड, 49,239 आयुष्मान कार्ड, 5,885 किसान सम्मान निधि, 98,319 परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 21 नई सड़कें, मोबाइल टावर, उप-स्वास्थ्य केंद्र और उचित मूल्य दुकानों ने जीवन बदल दिया है।

प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर छत्तीसगढ़ का बस्तर मानो अभिशप्त था, लेकिन आज निवेश का नया गंतव्य बन रहा है। नई औद्योगिक नीति, 2024-30 के तहत स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उद्योग, डेरी, पर्यटन और वेलनेस सेक्टर में 967 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। नगरनार स्टील प्लांट के आसपास 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र चिह्नित किया गया है। एमएसएमई और सेवा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये का निजी निवेश, नए उद्योगों से 2100 से अधिक रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। जगदलपुर में 350 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कालेज स्थापित होने जा रहा है। कुल 700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले ये प्रोजेक्ट बस्तर को मेडिकल हब बनाने की दिशा में कदम हैं। इसके साथ ही रोजगार, कौशल और उद्यमिता का विस्तार, 90,273 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, 39,137 युवाओं का नियोजन, आइटी, आटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, सोलर आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आधुनिक राइस मिल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड स्टोरेज किसानों की आय बढ़ा रहे हैं। एग्रीटेक परियोजनाएं कृषि को आधुनिक बना रही हैं। जब कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। सड़कें अच्छी हों। युवाओं को काम मिले तो किसी भी क्षेत्र की छवि दूसरे प्रदेशों के लोगों में सकरात्मक होती है। ऐसे में पर्यटन की संभावना बढ़ती है। बस्तर में भी यही हुआ है। अब पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर की पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने का प्रयास हो रहा है। धुड़मारास को यूनाइटेड नेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। इसके साथ ही चित्रकोट, तीरथगढ़, कांगेर घाटी में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। यहां एडवेंचर टूरिज्म, ग्लास ब्रिज, कनापी वाक, होम स्टे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पर्यटन से हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। साफ है कि सरकार अब केवल योजनाएं नहीं, बल्कि धरातल पर परिवर्तन ला रही है। जो माओवाद कभी भारत के भीतर सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती था, आज केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से सीमित क्षेत्र तक सिमट चुका है। अब विकास उसका स्थान ले रहा है।

अभियान

देव दर्शन के बाद का आचरण और अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव

हिंदू सनातन परंपरा में मंदिर केवल पत्थर और मूर्तियों का स्थान नहीं माना गया है, बल्कि उसे जीवंत चेतना और दिव्य ऊर्जा का केंद्र स्वीकार किया गया है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ मंदिर में प्रवेश करता है, तो वह अनजाने ही एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश कर जाता है। वहां गूंजते मंत्र, आरती की लौ, धूप की सुगंध और भक्तों की सामूहिक भावना मिलकर ऐसी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो मन और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव डालती है। इसी कारण शास्त्रों में यह बताया गया है कि मंदिर दर्शन के बाद व्यक्ति का आचरण अत्यंत संयमित और समझदारी भरा होना चाहिए, ताकि वह दिव्य प्रभाव नष्ट न हो।

अक्सर दैनिक जीवन में देखा जाता है कि लोग मंदिर से लौटते ही घर पहुंचकर तुरंत हाथ-पैर धो लेते हैं या स्नान कर लेते हैं। बाहरी दृष्टि से यह स्वच्छता का सामान्य नियम लगता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसका अर्थ कुछ और है। माना जाता है कि मंदिर की पवित्र भूमि पर चलते समय चरणों के माध्यम से जो सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, वह कुछ समय तक स्थिर रहना चाहती है। यदि व्यक्ति दर्शन के तुरंत बाद पानी से हाथ-पैर धो लेता है, तो वह

ऊर्जा जल्दी क्षीण हो सकती है। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि मंदिर से लौटने के बाद कम से कम कुछ समय तक पानी का प्रयोग न करें और शरीर को उस दिव्य प्रभाव के साथ सामंजस्य स्थापित करने दें। धार्मिक ग्रंथ यह भी बताते हैं कि मंदिर से आने के बाद व्यक्ति को सीधे सांसारिक कार्यों में नहीं उलझना चाहिए। उस समय मन अभी भी ईश्वर की उपस्थिति से प्रभावित होता है। यदि व्यक्ति कुछ देर शांत होकर बैठ जाए, आंखें बंद कर भगवान का नाम स्मरण करे और दर्शन के भाव को भीतर महसूस करे, तो वह ऊर्जा और भी गहराई से मन में उतर जाती है। यह प्रक्रिया केवल मानसिक शांति ही नहीं देती, बल्कि व्यक्ति के विचारों को भी शुद्ध करती है। माना जाता है कि इसी अवस्था में की गई प्रार्थना शीघ्र फलदायी होती है।

ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से मंदिर की ऊर्जा व्यक्ति की आभा को भी सशक्त बनाती है। आभा एक प्रकार का सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है, जो व्यक्ति के चारों ओर विद्यमान रहता है। देव दर्शन के बाद यह आभा अधिक तेज, स्वच्छ और संतुलित होती है। यदि इस अवस्था में तुरंत स्नान कर लिया जाए, तो यह संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि मंदिर से लौटते ही स्नान न करें, बल्कि कुछ समय बाद, जब मन स्थिर हो जाए और ऊर्जा अपने स्थान पर बैठ जाए, तभी जल का प्रयोग करें।

मंदिर से लौटकर घर में प्रवेश करने पर व्यक्ति को मन में श्रद्धा बनाए रखते हुए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। यह भाव रखना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से उसे दर्शन का सौभाग्य मिला। कुछ क्षण तक मौन रहना, मन को शांत रखना और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाना भी इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा करने से मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे घर के वातावरण में फैल जाती है।

इस तरह देखा जाए तो मंदिर जाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना है। दर्शन के बाद अपनाया गया संयम, धैर्य और शांति का व्यवहार उस साधना को पूर्णता देता है। जब व्यक्ति कुछ समय तक उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर स्थिर रहने देता है, तभी देव दर्शन का वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में मंदिर से लौटने के बाद के नियमों को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि इन्हीं नियमों से श्रद्धा, शुद्धता और आध्यात्मिक संतुलन की रक्षा होती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत में 'ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल' की 116वीं नेशनल एग्जीक्यूटिव बैठक का शुभारंभ किया

▸▸ देश के 16 राज्यों के महानगरों के महापौर एवं राज्य के शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई सहभागी हुए

▸▸ शहरों का सर्वग्राही आर्थिक, सामाजिक विकास तथा स्मार्ट, सस्टेनबल सिटी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री

▸▸ द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का मजबूत आधार है: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

-:मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरीकरण की चुनौतियों को अवसर में बदलकर गुजरात में वर्ष 2005 में 'शहरी विकास वर्ष' से मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट मॉडल की पहल की

▸▸ 2005 के 'शहरी विकास वर्ष' की दो दशक की सफलता के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 को 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मनाने से शहरों की स्वच्छता और फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में गति आई है

▸▸ प्रधानमंत्री के दिशादर्शन में गुजरात ने सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से शहरों के समग्र विकास के लिए 'स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना' की पहल की

▸▸ प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इन्क्लूसिव ग्रोथ के विचार को साकार करने के लिए छोटे शहरों के विकास को भी गति देते हुए नई महानगर पालिकाओं का गठन किया गया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि शहरों का सर्वग्राही आर्थिक, सामाजिक विकास तथा स्मार्ट, सस्टेनबल सिटी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने का मजबूत आधार है।

शनिवार को सूरत में आयोजित अखिल भारतीय 'मेयर्स परिषद' की 116वीं कार्यकारिणी बैठक के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अध्यक्ष के तौर पर संबोधित किया। शहरी विकास एवं वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, देश के 16 राज्यों के महानगरों के महापौर तथा परिषद के पदाधिकारी इस कार्यकारिणी बैठक में सहभागी हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरीकरण की चुनौतियों को अवसर में बदलकर गुजरात में वर्ष 2005 में शहरी विकास वर्ष के माध्यम से मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट मॉडल की शुरुआत की थी।

वेल प्लांड सिटी डेवलपमेंट के लिए बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को इसके परिणामस्वरूप गति मिली और 2005 के 'शहरी विकास वर्ष' की दो दशक की सफलता के चलते राज्य सरकार ने भी वर्ष 2025 को 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मनाया। श्री पटेल ने जोड़ा कि 2025 के इस 'शहरी विकास वर्ष' में शहरों की स्वच्छता तथा फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में तेजी आई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'मेयर्स परिषद' में शहरी विकास योजनाओं और लोगों के ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि करने वाली गुजरात के इनिशिएटिव्स की प्रभावशाली प्रस्तुति की।

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन से शहरों के सर्वग्राही विकास के लिए 'स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना' की पहल गुजरात ने की है। इस योजना में भौतिक सुविधाएं, सामाजिक आधारभूत संरचना के साथ अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, 'मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना' को प्राथमिकता देने से ईज ऑफ लिविंग बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने देश को शहरी क्षेत्रों में बीआरटीएस जनमार्ग और ई-सिटी बस सेवाओं का सफल मॉडल दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत अनेक आइकॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, जिनमें सूरत डायमंड बोर्स तथा रिवरफ्रंट गौरव के प्रतीक बने हैं।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इन्क्लूसिव ग्रोथ के विचार को साकार करने के लिए छोटे शहरों के विकास को भी गति दी गई है। राज्य में नई नौ महानगर पालिकाओं का गठन किया गया है और बड़े महानगरों की महानगर पालिकाओं ने इन नई महानगर पालिकाओं का हैंड होल्डिंग कर हॉलिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास किया है।

मुख्यमंत्री ने विकसित गुजरात की भूमिका को दर्शाते हुए कहा कि 2047 तक 'विकसित भारत' के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने में गुजरात को अग्रसर बनाए रखने के लिए 'अर्निंग वेल-लिविंग वेल' मंत्र के साथ 'विकसित गुजरात @2047' का रोडमैप तैयार किया है। इस अवसर पर शहरी विकास तथा वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने उपस्थित सभी महापौरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शहरीकरण की चुनौती को अवसर मानकर जल प्रबंधन, स्वच्छता, शिक्षा, आवास, सीवेज और ग्रीन एनर्जी सहित के कार्य करने से निश्चित रूप से सुसंचालित नगर नियोजन किया जा सकता है। उन्होंने जोड़ा कि पूरे देश में ग्रीन एनर्जी राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सोलर योजना में गुजरात की उपलब्धि अब अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्वरूप बनी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने 48 प्रतिशत शहरीकरण का लक्ष्य हासिल किया है तथा वर्ष 2047 तक 75 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। 'अखिल भारतीय मेयर्स परिषद' की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेणूबाला गुप्ता ने अपने प्रासंगिक संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात ने पूरे देश को विकास का एक नया मार्ग दिखाया है तथा गुजरात को देश के लिए रोल मॉडल बनाया है, जिससे अन्य नगरों के महापौरों को स्वच्छ, स्मार्ट व सुविधासंपन्न नगर के विकास के लिए मार्गदर्शन मिलेगा।

प्रासंगिक संबोधन में 'अखिल भारतीय मेयर्स परिषद' के महामंत्री श्री आशुतोष ने परिषद की स्थापना, कार्यों और उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी तथा शहरी विकास में परिषद के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

इस अवसर पर महापौर श्री दक्षेशभाई मावाणी ने कहा कि सूरत ने स्वच्छता, जल प्रबंधन और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्होंने जोड़ा कि विकास के निरंतर नए आयामों के साथ आगे बढ़ता सूरत देश के कई शहरों के लिए सकारात्मक सुधारों के माध्यम से अन्य शहरों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।

इस अवसर पर गुजरात की महानगर पालिकाओं के महापौर, सांसद श्री मुकेशभाई दलाल, विधायक श्री प्रविणभाई घोघारी, पूर्णेशभाई मोदी, संगीताबेन पाटील, पूर्व मंत्री श्री दर्शनाबेन जरदोश, सूरत महा नगरपालिका आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल, कलेक्टर श्री सौरभ पारधी, उप महापौर श्री नरेन्द्रभाई पाटिल, स्थायी समिति अध्यक्ष श्री राजनभाई देसाई, शहर संगठन प्रमुख श्री परेशभाई पटेल, मनपा में शासक पक्ष की नेता श्रीमती शशिबेन त्रिपाठी, सचेतक श्री धर्मेश वाणियावाला सहित सूरत महानगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

विरमगाम स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास : यात्रियों के लिए आधुनिक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्टेशन की दिशा में बड़ा कदम

2000 वर्गफीट का विशाल कंकॉर्स, 5000 वर्गफीट का पार्किंग क्षेत्र और 1460 वर्गफीट के डीलक्स प्रतीक्षालय का होगा समावेश

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, 160 स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें से गुजरात के 87 स्टेशन शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री ने इसी साल मई महीने में बीकानेर से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। जिसमें सामाख्याली सहित गुजरात के 18 स्टेशन शामिल है।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल का विरमगाम स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। विरमगाम रेलवे स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास 46.13 करोड़ की लागत से तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में विरमगाम स्टेशन पर 50 से अधिक ट्रेनें रुकती है। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 7000 यात्री आवागमन करते है। इसे अगले 45-50 वर्ष के यात्री भार को ध्यान में रखते हुए पुनर्विकसित किया जा रहा है। विरमगाम स्टेशन पर 40 फीट चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है जो प्लेटफॉर्मों के बीच सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करेगा।

यह स्टेशन अहमदाबाद–विरमगाम, विरमगाम–सुरेंद्रनगर, विरमगाम–मेहसाणा और विरमगाम–धांगधा–समाखियाली इन चार रेल मार्गों के जंक्शन पर स्थित है। यहाँ गेटवे डिस्ट्रिपार्क्स द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो सुविधा भी उपलब्ध है। जून 2023 में विरमगाम से मुंद्रा पोर्ट तक डबल-स्टैक रेल परिवहन सेवाएँ शुरू कीं, जिसका उद्देश्य अपने निर्यात-आयात (EXIM) व्यापार ग्राहकों के लिए परिचालन दक्षता बढ़ाना और लॉजिस्टिक लागत कम करना है।

विरमगाम स्टेशन का पुनर्विकास कार्य यात्री सुविधाओं, सुरक्षा तथा स्टेशन के सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए तेजी से प्रगति पर है। यह कार्य स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित तथा दिव्यांगजन अनुकूल बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

पूर्ण किए गए कार्य

▸▸ नए स्टेशन भवन की संरचना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

▸▸ नए स्टेशन भवन का प्लास्टर एवं टाइल्स लगाने का कार्य पूरा हो गया है।

▸▸ प्लेटफॉर्म पर शेड (शेल्टर) का कार्य पूरा कर लिया गया है।

▸▸ पुराने फुट ओवर ब्रिज (FOB) को सुरक्षित रूप से हटाया जा चुका है।

▸▸ नए विद्युत खंभों (इलेक्ट्रिक मस्त) की नींव का कार्य पूरा हो चुका है।

प्रगति पर कार्य

▸▸ नए स्टेशन भवन में आंतरिक एवं शेष समापन कार्य प्रगति पर है।

▸▸ यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए नए फुट ओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण कार्य जारी है।

▸▸ स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया तथा पार्किंग क्षेत्र का विकास कार्य जारी है।

▸▸ प्लेटफॉर्म सतह में सुधार का कार्य किया जा रहा है, जिससे चलने में सुविधा और सुरक्षा बढ़ेगी।

▸▸ स्टेशन पर प्रकाश व्यवस्था के उन्नयन हेतु नए विद्युत खंभों एवं हाई मस्त लाइट्स की स्थापना का कार्य चल रहा है।

▸▸ दिव्यांगजन के लिए टैक्टाइल टाइल्स, साइनज, हैंड रेल, समर्पित पार्किंग आदि सुविधाओं के विकास का कार्य प्रगति पर है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन (क्षेत्र/आकार):

▸▸ 4400 वर्गफीट की विशाल स्टेशन बिल्डिंग यात्रियों को आधुनिक एवं सुव्यवस्थित सुविधाएँ प्रदान करेगी।

▸▸ 20-20 फीट चौड़े प्रवेश/निकास द्वार यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाएंगे।

▸▸ 5000 वर्गफीट का पार्किंग क्षेत्र अधिक वाहनों को समायोजित करेगा।

▸▸ 13 फीट चौड़ी पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ लेन वाहनों की आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाएगी।

▸▸ 2200 वर्गफीट का पोर्च यात्रियों को मौसम से सुरक्षा एवं आरामदायक प्रवेश प्रदान करेगा।

▸▸ 2000 वर्गफीट का विशाल कंकॉर्स यात्रियों को अधिक विस्तृत और आरामदायक स्थान उपलब्ध कराएगा।

▸▸ प्लेटफॉर्मों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स का प्रावधान

▸▸ प्लेटफॉर्म नं 2 और 3 की लंबाई में 100 फीट तक विस्तार

▸▸ 336 वर्गफीट का प्रतीक्षालय बैठने और विश्राम के लिए आरामदायक सुविधा प्रदान करेगा।

▸▸ 570 वर्गफीट का कैफेटेरिया साफ-सुथरे एवं सुविधाजनक भोजन विकल्प उपलब्ध कराएगा।

▸▸ 730 वर्गफीट के डीलक्स एसी एवं नॉन-एसी प्रतीक्षालय शांत और आरामदायक वातावरण में प्रतीक्षा की सुविधा देंगे।

▸▸ प्लेटफॉर्म 1 से 5 तक 38000 वर्गफीट क्षेत्र में कवर शेड यात्रियों को मौसम से सुरक्षा प्रदान करेगा।

▸▸ 430 वर्गफीट का शौचालय ब्लॉक स्वच्छता एवं सुविधा को और बेहतर बनाएगा।

▸▸ दिव्यांगजन हेतु 03 समर्पित पार्किंग स्लॉट उनकी पहुँच और सुविधा को और बेहतर बनाएंगे।

विस्तृत सर्कुलेटिंग एरिया के विकास से स्टेशन परिसर में वाहनों की आवाजाही अधिक सुव्यवस्थित होगी, जिससे स्टेशन तक पहुँचने और बाहर निकलने की सुविधा में सुधार होगा। उन्नत प्रतीक्षालय बेहतर बैठने की सुविधा, उचित वेंटिलेशन और शांत वातावरण प्रदान करेंगे, जिससे यात्रा अनुभव अधिक सुखद बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत एपीएमसी द्वारा निर्मित राज्य के पहले एलिवेटेड मार्केट यार्ड का उद्घाटन किया

▸▸ टू-वे रैम्प वाली बिल्डिंग में हैं अत्याधुनिक सुविधाएं : भारी वाहन पहली मंजिल तक सीधे दुकानों के सामने पहुंच सकते हैं

▸▸ राज्य के किसानों को सहूलियत, सुरक्षा और कृषि उपजों का उचित मूल्य मिले, ऐसी पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्था विकसित की जा रही है : कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▸▸ सूरत एपीएमसी मार्केट के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के हिस्से के रूप में एलिवेटेड मार्केट यार्ड का निर्माण

▸▸ मार्केट यार्ड में आने वाले किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक उपचार केंद्र और बीज वितरण केंद्र का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▸▸ श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करके खेती में उत्पादन, सस्टेनेबिलिटी और बाजार की उपलब्धता बढ़ रही है

▸▸ 1951 में केवल 15 हजार रुपए की आय के साथ शुरू हुई सूरत एपीएमसी आज सहकारिता के वटवृक्ष में बदल गई है

▸▸ राज्य सरकार 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र के साथ कृषि में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दे रही है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति (एपीएमसी) सूरत की ओर से नवनिर्मित राज्य के सबसे बड़े और सर्वप्रथम एलिवेटेड यानी पहली मंजिल तक भारी वाहनों का आवागमन सुनिश्चित करने वाले अत्याधुनिक मार्केट यार्ड का लोकार्पण किया।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सूरत एपीएमसी मार्केट के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के हिस्से के रूप में निर्मित इस अत्याधुनिक एलिवेटेड मार्केट यार्ड में आने वाले किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक उपचार केंद्र और बीज वितरण केंद्र का भी लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने एलिवेटेड स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एपीएमसी की सराहना की, जिसमें बड़े ट्रक और भारी वाहनों की आसान आवाजाही तथा प्रवेश एवं निकास का इस प्रकार सुव्यवस्थित आयोजन किया गया है कि आने वाले कई वर्षों तक कोई अव्यवस्था नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1951 में केवल 15 हजार रुपए की आय के साथ शुरू हुई सूरत एपीएमसी आज सहकारिता के वटवृक्ष में बदल गई है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के अधिकतम उपयोग के जरिए किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र के साथ देश में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करके सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाया गया है, जिससे किसानों और पशुपालकों की आय और जीवन स्तर को सुधारने वाले महत्वपूर्ण कार्य को और व्यापक और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सका है।

मुख्यमंत्री ने संपूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी व्यवस्था तथा यहां कृषि उपजों की बिक्री के लिए आने वाले किसानों को आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बधाई दी। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि इन सुविधाओं के चलते महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के किसान भी यहां अपनी कृषि उपज बेचने के लिए आकर्षित हुए हैं।

उन्होंने गर्व से कहा कि रोजाना 12 से 15 हजार लोगों की आवाजाही के साथ यह मार्केट यार्ड पिछले दो वर्षों से आय की दृष्टि से गुजरात में अव्वल स्थान पर है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कृषि में मूल्य संवर्धन की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है। सरकार ने एग्रो और फल प्रसंस्करण श्रृंखला स्थापित कर आम, चीकू, सब्जियों और लहसुन आदि के लिए स्पेशल एग्री एक्सपोर्ट जोन भी विकसित किए हैं।

उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके खेती में उत्पादन, सस्टेनेबिलिटी और बाजार की उपलब्धता बढ़ रही है। किसान ई-मित्र जैसी एआई-आधारित सेवाओं के जरिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के बारे में आसान भाषा में जानकारी मिल रही है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के बाद राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषित किया गया दस हजार करोड़ रुपए का बड़ा कृषि सहायता पैकेज किसानों को इस संकट से उबारने में बहुत उपयोगी साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान मानधन, पर ड्रॉप-मोर क्रॉप, नेशनल बाम्बू मिशन ओर नमो ड्रोन दीदी सहित लगभग 28 से अधिक योजनाओं एवं अभियानों के जरिए खेती एवं किसान विकास को नई दिशा दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्लाइमेट चेन्ज के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रही है, जो भूमि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने सभी से स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ विकसित गुजरात से विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

इस अवसर पर कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि राज्य सरकार और सहकारी क्षेत्र इस बात का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को नई सुविधाएं, आधुनिक व्यवस्थाएं और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और उनकी आय में वृद्धि हो। इसका जीवंत उदाहरण सूरत की एपीएमसी मार्केट है। उन्होंने इस मार्केट में आधुनिकता के साथ-साथ किसान-उन्मुख सुविधाएं और व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं।

कृषि मंत्री ने कहा कि सूरत एपीएमसी मार्केट यार्ड राज्य का सबसे अधिक कमाई करने वाला यार्ड है, जो सहकारिता की शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। यह कमाई किसी एक व्यक्ति या संस्था की नहीं, बल्कि पूरी सहकारी व्यवस्था और किसानों की है। उन्होंने अतीत की विकट स्थिति की याद दिलाते हुए कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में राज्य के मार्केट यार्डों में उचित शेड, बारिश या मौसम संबंधित परिस्थितियों में कृषि उत्पादों को रखने की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज मार्केट यार्डों की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। अब ऐसी पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं, जिनमें किसानों को सहूलियत, सुरक्षा और कृषि उत्पादों का समुचित मूल्य मिलता है।

विधायक और सूरत एपीएमसी के चेयरमैन संदीपभाई देसाई ने स्वागत भाषण में कहा कि सूरत एपीएमसी में देश के 15 राज्यों से किसान और बागायतदार अपने उत्पाद बेचने के लिए आते हैं। अत्याधुनिक एलिवेटेड मार्केट यार्ड में 100 फुट चौड़ा रैम्प बनाया गया है, जिससे टैम्पो और ट्रक जैसे वाहन सीधे पहली मंजिल पर दुकानों के सामने जाकर खड़े हो सकते हैं। इस सुविधा से कृषि उपजों को लाने-ले जाने में लगने वाले समय की बचत होगी और यातायात की समस्या से निजात मिलेगी तथा कृषि उपजों को सीधे व्यापारियों की दुकानों पर उतारा जा सकेगा।

श्री देसाई ने कहा कि एलिवेटेड मार्केट यार्ड के लिए केंद्र सरकार ने 19 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। मार्केट यार्ड की पहली मंजिल पर 108 हाईटेक दुकानें हैं, जिनमें विशाल स्टोर रूम, मार्केट में पहली मंजिर तक किसान और व्यापारी अपने वाहन लेकर जा सकें, इसके लिए टू-वे रैम्प, माल-समान ले जाने के लिए लिफ्ट, पैसेंजर लिफ्ट, आरसीसी रोड, पहली मंजिल पर 200 कार और 4000 दोपहिया वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग एरिया, मार्केट यार्ड में आने वाले किसानों, व्यापारियों तथा श्रमिकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक उपचार केंद्र और किसान मित्रों के लिए बीज वितरण केंद्र जैसी सुविधाएं किसानों और वेंडर्स के लिए स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, आदिजाति विकास मंत्री श्री नरेशभाई पटेल, सांसद श्री मुकेशभाई दलाल, प्रभुभाई वसावा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री भाविनीबेन पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, विधायक सर्वश्री कुंवरजीभाई हळपति, गणपतसिंह वसावा, मोहनभाई ढोडिया, ईश्वरभाई परमार, विनोदभाई मोरड़िया, अरविंदभाई राणा, कांतिभाई बलर, मनुभाई पटेल, एपीएमसी उपाध्यक्ष श्री हर्षद पटेल, सूरत सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री भीखाभाई पटेल, सहकारी अग्रणी श्री रमणभाई जानी, एपीएमसी के निदेशकगण, जिला संगठन प्रमुख श्री भरत राठोड़, कई अग्रणी और किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

कोटा में ज्वेलरी शॉप पर मौत को मात, समय पर दिए गए सीपीआर से व्यापारी की बची जान

राजस्थान के कोटा शहर में रामपुरा बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब जयपुर से आए एक व्यापारी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वे देखते ही देखते बेहोश होकर काउंटर पर गिर पड़े। पल भर में माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन सूझबूझ, साहस और सही समय पर लिए गए फैसले ने एक व्यक्ति की जान बचा ली। यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों के लिए सीपीआर जैसी जीवन रक्षक तकनीक के महत्व का जीवंत उदाहरण बन गई है।

जानकारी के अनुसार, जयपुर के झोटवाड़ा निवासी राजकुमार सोनी हर दो से चार महीने में कोटा आकर ज्वेलरी शॉप्स में नगीने और स्टोन दिखाने का काम करते हैं। गुरुवार दोपहर करीब दो बजे वे रामपुरा बाजार स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में स्टोन दिखा रहे थे। इसी दौरान वे कुर्सी पर बैठे-बैठे अचानक असहज महसूस करने लगे और कुछ ही सेकंड में काउंटर की ओर गिर पड़े। पहले तो वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बेहोशी की हालत में पड़े रहे, तो स्थिति की गंभीरता साफ हो गई।

शोरूम में मौजूद कर्मचारियों और मालिक परिवार के लोग तुरंत उनके पास पहुंचे। सभी ने मिलकर उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी सांसें बेहद कमजोर हो चुकी थीं। हालात को भांपते हुए शोरूम मालिक विमल जैन के बेटे वरुण जैन ने बिना एक पल गंवाए सीपीआर देना शुरू कर दिया। वरुण जैन को पहले से सीपीआर का प्रशिक्षण प्राप्त था और वे इससे संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों और वीडियो के जरिए जानकारी भी लेते रहते हैं। इसी प्रशिक्षण ने उस समय एक अमूल्य भूमिका निभाई। लगभग एक से डेढ़ मिनट तक लगातार सीपीआर देने के बाद राजकुमार सोनी की सांसें वापस आने लगीं और उनके शरीर में हलचल दिखाई देने लगी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ ही देर में उनकी स्थिति में सुधार आने लगा और वे होश में आ गए। इस पूरी घटना के दौरान शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में हर दृश्य कैद हो गया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि समय पर दिया गया सीपीआर किस तरह एक इंसान की जान बचाने में निर्णायक साबित हुआ। शोरूम मालिक विमल जैन ने बताया कि शुरुआत में उन्हें अंदेशा हो गया था कि मामला हार्ट अटैक का हो सकता है, इसलिए बिना देर किए सीपीआर देना ही सबसे सही कदम था। उन्होंने कहा कि अगर कुछ मिनट और देर हो जाती, तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकता था। इस दौरान शोरूम के अन्य कर्मचारियों ने भी सहयोग किया और माहौल को संभाले रखा। घटना के बाद व्यापारी को अस्पताल ले जाने की बात कही गई, लेकिन राजकुमार सोनी ने खुद को बेहतर महसूस करने की बात कहते हुए जाने से इनकार कर दिया और कुछ देर आराम करने के बाद पैदल ही दुकान से बाहर निकल गए। शुक्रवार सुबह वरुण जैन की उनसे फोन पर बातचीत भी हुई, जिसमें राजकुमार सोनी ने बताया कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें अब किसी तरह की परेशानी नहीं है।

यह घटना न केवल एक जान बचने की कहानी है, बल्कि आम लोगों के लिए एक बड़ा संदेश भी है कि सीपीआर जैसी बुनियादी चिकित्सा जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। सही समय पर लिया गया सही निर्णय और थोड़ी सी जागरूकता किसी की जिंदगी बचा सकती है। कोटा की इस ज्वेलरी शॉप में जो हुआ, वह आज समाज के लिए एक सीख बनकर सामने आया है कि आपात स्थिति में घबराने के बजाय समझदारी और प्रशिक्षण से बड़ा चमत्कार किया जा सकता है।

आकृति आर्ट फाउंडेशन द्वारा 23 वीं अंतरष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का 16 दिसम्बर से मुंबई में आयोजन

(जीएनएस)। मुंबई, 13 दिसम्बर। देश की प्रमुख सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक संस्था *"आकृति आर्ट फाउंडेशन"* द्वारा अपनी 23 वीं अंतर्राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई में 16 दिसम्बर, 2025 से 21 दिसम्बर, 2025 तक किया जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए आकृति आर्ट फाउंडेशन के संस्थापक डायरेक्टर मनमोहन जायसवाल ने बताया कि यह संस्था पिछले 18 वर्षों से कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। इसी क्रम में संस्था की 23 वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित मेकर चैम्बर्स की आर्ट गैलेरी में लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दुबई और पोलैंड से तकरीबन 40 प्रतिष्ठित कलाकार भाग ले रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि वे प्रत्येक वर्ष दो आर्ट एग्जिबिशंस का आयोजन करते हैं। इनमें देश- विदेश से आने वाले कलाकारों को अपनी

खूबसूरत कला के प्रदर्शन का सुअवसर मिलता है। साथ ही उनकी संस्था विभिन्न अवॉर्ड शो, म्यूजिकल शो और आध्यात्मिक इवेंट्स का भी आयोजन करती आई है। उन्होंने बताया कि वे जल्दी ही अपनी टीम के साथ सभी कलाकारों के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आसानी से दुनिया के किसी भी कोने तक कलाकारों की कृतियाँ पहुँचाई जा सकती हैं। 23 वीं प्रदर्शनी में सुविख्यात चित्रकार एम एफ हुसैन, जामिनी रॉय, एस एच राजा, सोहन कुमार, पूर्वा तेनानी, प्रियेश, प्रधन्या पंडित, अनीता गोयल, संजना रामचंदानी, वैशाली शाह, प्रवीण पांडे, निशा गांधी, सलोनी गुप्ता, शोभना मेहता, सुनामदिनी जयंत, राजवी गांधी, निराली मोदी, राखी संघवी, रितिका सिंह, शेखर बर्वे, नंदा पाठक, सुमेध उन्नावने मयूर श्रीवंधनकर, नवाब जहान, तानिया फटनानी, ध्यानज्योति निंबालकर, शिवानी धुरिया, प्रीति शाह, आरती चोरड़िया, रूपाली मिस्त्री और श्रुति सोमन की पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया जायेगा। प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में बहुत से कला प्रेमी, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट तथा संगीत और साहित्य जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दीप प्रज्ज्वलन के साथ इस भव्य प्रदर्शनी की शुरुआत होगी। यह प्रदर्शनी 16 से 21 दिसम्बर, 2025 तक रोज़ाना दोपहर 12 से रात्रि 8 बजे तक सभी कलाप्रेमी दर्शकों के निःशुल्क अवलोकनार्थ खुली रहेगी।

जामनगर में प्रभारी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया की अध्यक्षता में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित

▸▸ जिला स्तरीय कार्यक्रम में जामनगर की 9 कंपनियों द्वारा 5716 करोड़ के एमओयू किए गए

▸▸ उद्योगपति संपत्ति के सृजनकर्ता और देश की प्रगति के प्रमुख वाहक हैं: प्रभारी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया

(जीएनएस)। गांधीनगर : जामनगर में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला के अंतर्गत राज्य के वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माननीय मंत्री तथा जामनगर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया की अध्यक्षता में लेउआ पाटीदार समाज भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान जिला उद्योग केंद्र और विभिन्न 9 कंपनियों के बीच कुल 5716 करोड़ की राशि के एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। इनमें विंड-सोलर पावर हाइब्रिड प्रोजेक्ट (नवीकरणीय ऊर्जा) सेक्टर में ओपविंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (3368 करोड़), जामनगर रिन्यूएबल्स वन एंड टू प्राइवेट लिमिटेड (1703 करोड़) तथा सुजलॉन वेस्टर्न इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड (600 करोड़) द्वारा आगामी तीन वर्षों में विंड-सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित किया जाएगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से अनुमानित रूप से 1725 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

इसके अलावा, इंजीनियरिंग, ऑटो एवं अन्य उद्योग क्षेत्रों में शिव ओम ब्रास इंडस्ट्रीज (25 करोड़), मेटालेक्स एक्सट्रूज़न (6.5 करोड़), एटलस मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (5 करोड़), रेमबेम पी.जी.एम. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (5 करोड़) तथा यल्लो गोल्ड मेटल प्राइवेट लिमिटेड (3.5 करोड़) द्वारा एल्युमिनियम एक्सट्रूज़न प्लांट, एल्युमिनियम एवं कॉपर लग्स, ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग, केमिकल प्रोडक्ट्स और ब्रास पार्ट्स के क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इनसे अनुमानित रूप से 400 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इन सभी परियोजनाओं के वर्ष 2026 में प्रारंभ होने की संभावना है। इसके साथ ही माननीय मंत्री द्वारा श्री वाजपेयी बैंकेबल योजना के लाभार्थियों को व्यवसाय हेतु लोडिंग वाहनों की चाबियां भी प्रदान की गईं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये गुजरात के विकास की दृष्टि, आत्मनिर्भरता के संकल्प और विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ की गई वाइब्रेंट गुजरात पहल ने आज गुजरात को वैश्विक निवेशकों के लिए एक पसंदीदा केंद्र बना दिया है।

जामनगर जिला औद्योगिक दृष्टि से एक विशिष्ट पहचान रखता है। चाहे ब्रास पार्ट उद्योग हो या निर्माण क्षेत्र, रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग हों, बंदरगाह आधारित गतिविधियाँ हों या पारंपरिक कारीगरी, जामनगर ने हमेशा विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। यहाँ के उद्योगपतियों की मेहनत और कौशल ने जामनगर को 'ब्रास सिटी ऑफ इंडिया' के रूप में पहचान दिलाई है।

राजकोट में आयोजित होने वाली रीजनल समिट के माध्यम से राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर मौजूद औद्योगिक संभावनाओं की पहचान करना, स्थानीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन को और अधिक गति देना है। यह विशेष रूप से एमएसएमई, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है।

श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने आगे कहा कि उद्योगपति संपत्ति के सृजनकर्ता और देश की प्रगति के प्रमुख वाहकों में से एक हैं। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में उद्योगपतियों की अहम भूमिका होती है। जामनगर में ऑयल रिफाइनरी, निर्माण कार्यक्षेत्र और ब्रास पार्ट उद्योगों के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जामनगर के उद्योगपतियों ने तकनीकी उन्नयन और बाजार अनुसंधान के साथ आधुनिक तकनीकों को अपने व्यवसाय में अपनाया है। गुजरात को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

जामनगर जिले में आने वाले दिनों में नए उद्योगों, नई तकनीकों और नए रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होने की प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसे में माननीय मंत्री द्वारा राजकोट में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में जामनगर जिले के उद्योगपतियों से सक्रिय सहभागिता करने की अपील की गई।

शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रिवाबा जाडेजा ने कहा कि बांधणी उद्योग जामनगर की सांस्कृतिक पहचान है। जामनगर में बांधणी उद्योग के चलते महिलाओं को रोजगार मिला है और वे आत्मनिर्भर बनी हैं। जामनगर की बांधणी को प्राप्त जीआई टैग तथा जामनगर के ब्रास पार्ट उद्योग में कार्यरत कारीगरों और उद्योगपतियों की मेहनत के परिणामस्वरूप यहाँ इसरो और नासा जैसी संस्थाओं के लिए भी ब्रास पार्ट्स का निर्माण हुआ है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। जामनगर का ब्रास पार्ट उद्योग और बांधणी उद्योग दोनों ही गुजरात की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का सशक्त प्रतीक हैं। एक ओर आधुनिक उद्योगों से रोजगार और निर्यात में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक कला के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी हो रहा है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस गुजरात सरकार की दूरदर्शिता, विकास के प्रति प्रतिबद्धता और सर्वांगीण प्रगति का सशक्त प्रतिबिंब है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों की ताकत, संभावनाओं और स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा। उद्योगपतियों की सफलता की गाथाओं की प्रस्तुति के अंतर्गत जामनगर फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रामजीभाई गढ़िया तथा मैसर्स माइक्रोटेक मेटल इंडस्ट्रीज के श्री अशोकभाई डोमडिया ने ब्रास उद्योग से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इसके पश्चात विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात स्टार्टअप इकोसिस्टम, एसएमई इनोवेशन लाइक ए कॉर्पोरेट इनोवेशन, ग्लोबल परिदृश्य एवं निर्यात, क्रेडिट लिंकेज सेमिनार, पीएमएफएमई योजना, युवाओं को कौशल प्रदान करना एवं रोजगार के अवसर सृजित करना, वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस पर प्रस्तुति तथा जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इस कार्यक्रम में लगभग 25 विभिन्न स्टॉलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें ब्रास पार्ट्स से संबंधित स्टॉल, बांधणी के स्टॉल, हस्तकला के स्टॉल सहित विविध क्षेत्रों के स्टॉल शामिल थे। माननीय मंत्रीगण एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने इन स्टॉलों का अवलोकन किया तथा संबंधित प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम के दौरान iNDEXTb के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री के. सी. संपत द्वारा प्रासंगिक उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मेयबेन गरसर, विधायक श्री दिव्येशभाई अकबरी, कलेक्टर श्री केतन ठक्कर, जिला विकास अधिकारी श्री अंकित पन्नु, डिप्टी मेयर श्रीमती कृष्णाबेन सोंढा, एएसपी श्रीमती प्रतिभा, अग्रणी समाजसेवी श्रीमती बीनाबेन कोठारी एवं डॉ. विनोदभाई भंडेरी, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री रमणिकभाई अकबरी, जीआईडीसी फेज़ 2 एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विष्णुभाई पांभर, लघु उद्योग भारती एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जयेशभाई संघाणी, जामनगर सहकारी उद्योग संघ लिमिटेड के अध्यक्ष श्री धीरजलाल कारिया, एम. पी. शाह म्यूनिसिपल उद्योगनगर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सरदारसिंह जाडेजा सहित विभिन्न एसोसिएशनों के पदाधिकारी, अधिकारीगण, उद्योगपति तथा आमंत्रित अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का महाआंदोलन, 17 दिसंबर का अल्टीमेटम; हनुमानगढ़ का टिब्बी इलाका छावनी में तब्दील

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब बड़े आंदोलन और हिंसक टकराव का रूप ले चुका है। टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में बुधवार को आयोजित महापंचायत के बाद हालात अचानक बेकाबू हो गए। किसानों की नाराजगी इतनी तेज थी कि बातचीत विफल होते ही विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और देखते ही देखते पूरा इलाका तनाव की चपेट में आ गया। इस घटनाक्रम के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रख दिया है और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।

दरअसल, दोपहर में एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति और जिला प्रशासन के बीच वार्ता हुई थी, लेकिन यह बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। किसान फैक्ट्री के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की लिखित गारंटी की मांग पर अड़े रहे, जबकि प्रशासन की ओर से आश्वासन के अलावा कोई स्पष्ट आदेश सामने नहीं आया। इसी असंतोष के बीच बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ निर्माणाधीन फैक्ट्री की ओर बढ़ गए। हालात उस समय और बिगड़ गए जब गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों की मदद से फैक्ट्री की चारदीवारी गिरा दी और अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया।

उग्र भीड़ ने कम से कम दस वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिनमें एक जेसीबी मशीन, कई कारें, दो मोटरसाइकिलें और एक पुलिस जीप शामिल बताई जा रही है। इसके अलावा कई निजी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। आग की लपटें और धुएं के गुबार दूर-दूर तक नजर आने लगे, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को मजबूरन सख्ती करनी पड़ी। पहले आंसू गैस के गोले दागे गए और जब भीड़ पीछे नहीं हटी तो लाठीचार्ज किया गया।

इस भिड़ंत में संगरिया से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया भी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, पुलिस के कम से कम पांच जवानों के घायल होने की खबर है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हिंसा के बाद प्रशासन ने एहतियातन टिब्बी और आसपास के गांवों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। स्कूल, कॉलेज, बाजार और दुकानें भी अस्थायी रूप से बंद करा दी गई हैं। सड़कों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार गश्त जारी है, जिससे पूरा इलाका छावनी जैसा नजर आने लगा है।

किसानों ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण पर रोक लगाने का लिखित आदेश नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति ने बड़े महाआंदोलन का ऐलान करते हुए 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि यह सिर्फ एक फैक्ट्री का मुद्दा नहीं है, बल्कि पर्यावरण, भूजल संरक्षण और किसानों की जमीन की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। उनका आरोप है कि फैक्ट्री से इलाके के पानी और खेती पर गंभीर असर पड़ेगा।

दूसरी ओर, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बयान जारी कर कहा है कि प्रशासन शांतिपूर्ण बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कानून व्यवस्था से खिलवाड़ और हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हनुमानगढ़ का यह इलाका तनावपूर्ण शांति के दौर से गुजर रहा है और सबकी नजरें 17 दिसंबर पर टिकी हुई हैं, जब किसानों ने अपने महाआंदोलन के जरिए आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने शहरी विकास वर्ष के उत्सव के अंतर्गत सूरत वासियों को 600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट दी

▸▸ सूरत महानगर पालिका और सुडा के 249 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 109.51 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अर्बन रिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूआरडीसीएल) के अनुमानित 242 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया

▸▸ प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप का लाभ आज पूरे देश के साथ गुजरात को मिल रहा है, सभी शहरी जन स्वच्छता को अपना स्वभाव बनाएं: मुख्यमंत्री

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्यों के शहरों के विकास को गति देने तथा शहरी जनों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने शनिवार को 'शहरी विकास वर्ष–2025' के उत्सव के अंतर्गत सूरत महानगर पालिका और सुडा (सूरत शहरी विकास प्राधिकरण) के कुल 249 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 109.51 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने अर्बन रिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूआरडीसीएल) द्वारा साकार होने वाले अनुमानित 242 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में आयोजित समारोह में सूरत वासियों को 600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप का लाभ आज पूरे देश के साथ गुजरात को मिल रहा है। सूरत के साथ पूरा गुजरात तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में सूरत ने अपनी पहचान बनाई है। इस दौरान श्री पटेल ने सभी लोगों से स्वच्छता को स्वभाव में अपनाने का आग्रह किया। सूरत का आउटडोर रिंग रोड पूर्ण होने से ट्रैफिक में कमी के साथ लोगों की सुविधाओं में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में सामान्य व्यक्ति को केंद्र में रखकर विकास आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि एक समय था जब एक लाख रुपए के कार्य के लिए भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जबकि आज एक करोड़ रुपए के कार्य आसानी से हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव आया है, ऐसे में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने सभी से वृक्षारोपण कर ग्रीन कवर बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने वर्षा जल के पूर्ण उपयोग से जल संचय मां सभी की भागीदारी की भी अपेक्षा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के कारण आज कच्छ एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बना है। एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क खावड़ा में साकार हुआ है। ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। एक समय राज्य के समुद्र तटों के प्रति उदासीनता थी, आज गुजरात का समुद्र तट समृद्धि का गेट-वे बन गया है।

सूरत जिला प्रभारी एवं वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि वर्ष 2025–26 में राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपए का बड़ा बजट आवंटित किया है। नई महानगर पालिकाओं के विकास के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। महानगर पालिकाओं के नव-गठन के साथ ही बजट उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके अनुरूप आधारभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं की अग्रिम योजना बनाई गई है। भरूच और उमरगाम के बीच सूरत विकास का केंद्र बिंदु है, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में विकास और पर्यटन से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। सूरत विश्व के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है।

महानगर पालिका कमिश्नर श्रीमती शालिनी अग्रवाल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि सूरत शहर के नए क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य उपयोगी सिद्ध होंगे। वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 'अर्निंग वेल और लिविंग वेल' के मंत्र के साथ रीजनल डेवलपमेंट के छह प्लान के अंतर्गत दक्षिण गुजरात का विकास विजन शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा, जो विकास का एक महत्वपूर्ण रोडमैप बनेगा।

सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलाजेशन, जल प्रबंधन में सुधार, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि तथा शहर के आधारभूत नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए विकास कार्यों की सौगात दी गई। सूरत महानगर पालिका के विभिन्न जोन में बने प्रमुख कार्यों में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, गंदे पानी के निपटान के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज लाइन, हेल्थ सेंटर, फायर स्टेशन, वेंडिंग मार्केट तथा वर्षा जल निकासी के लिए बॉक्स कल्वर्ट सहित के कार्यों का शिलान्यास किया गया।

अर्बन रिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट फेज–2 के अंतर्गत 184.20 करोड़ रुपए की लागत से सचिन–पलसाणा से सचिन कडोदरा जंक्शन आउटर रिंग रोड का कार्य तथा 57.65 करोड़ रुपए की लागत से सूरत–कडोदरा रोड आउटर रिंग रोड पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण कार्य का शिलान्यास शामिल है। सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (सुडा) द्वारा शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न टीपी स्कीमों के तहत चार लेन सड़कों, डामर रोड, सड़कों के रिसर्फेसिंग कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करते हुए सूरत महानगर पालिका द्वारा नागरिकों को मनपा की विभिन्न सेवाएं सरल, तेज और पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट की ऑनलाइन पेमेंट सुविधा का लॉन्च किया।

कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी, सांसद श्री मुकेश दलाल, मेयर दक्षेश मावाणी, विधायक श्री पूर्णेश मोदी, श्री संदीप देसाई, श्री ईश्वर परमार, श्री कांतीभाई बलर, श्री संगीता बेन पाटील, उप महापौर नरेन्द्र पाटील, स्थायी समिति के चेयरमैन श्री राजन पटेल, जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी, कॉरपोरेटर सहित पदाधिकारी व शहरीजन उपस्थित रहे।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा में 2391 रुपये और चांदी वायदा में 20804 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 204 रुपये फिसला

कमोडिटी वायदाओं में 359185.31 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 1803312.3 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 261454.80 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 32563 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 5 से 11 दिसंबर के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 2162557.67 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 359185.31 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 1803312.3 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 32563 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 34415.85 करोड़ रुपये का हुआ।

आलोच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 261454.80 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 129897 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 132574 रुपये के ऑल टाइम हाई और 129101 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 130078 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2391 रुपये या 1.84 फीसदी की तेजी के संग 132469 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में 1509 रुपये या 1.45 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 105706 रुपये प्रति 8 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 191 रुपये या 1.46 फीसदी की तेजी के संग 13239 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर सप्ताह के अंत में पहुंचा। सोना-मिनी जनवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 128785 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 130988 रुपये के उच्च और 127833 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 2011 रुपये या 1.56 फीसदी की मजबूती के साथ 130905 रुपये प्रति 10 ग्राम बंद हुआ। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 129048 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 131290 रुपये के उच्च और 128140 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 129192 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 1945 रुपये या 1.51 फीसदी की बढ़त के साथ 131137 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 179509 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 199220 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 179200 रुपये पर पहुंचकर, 178138 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 20804 रुपये या 11.68 फीसदी ऊछलकर 198942 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 20273 रुपये या 11.33 फीसदी की तेजी के संग 199210 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 20280 रुपये या 11.33 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 199223 रुपये प्रति किलो पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ।

मेटल वर्ग में 28459.67 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में 38.25 रुपये या 3.56 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1111.85 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 11.85 रुपये या 3.84 फीसदी की मजबूती के साथ सप्ताह के अंत में 320.1 रुपये प्रति किलो बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 2.45 रुपये या 0.88 फीसदी बढ़कर 280.7 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा दिसंबर वायदा सप्ताह के अंत में 1.15 रुपये या 0.63 फीसदी घटकर 181.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 69252.56 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5363 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 5449 रुपये और नीचे में 5160 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 204 रुपये या 3.79 फीसदी गिरकर 5179 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 201 रुपये या 3.74 फीसदी की गिरावट के साथ सप्ताह के अंत में 5180 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा 453.2 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 494.9 रुपये और नीचे में 380 रुपये पर पहुंचकर, 447.4 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 66.3 रुपये या 14.82 फीसदी गिरकर 381.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 66.3 रुपये या 14.81 फीसदी लुढ़ककर 381.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू सप्ताह के अंत में बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 904 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 7.8 रुपये या 0.86 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 911 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 108824.90 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 152629.90 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 22994.57 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 1707.58 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 328.54 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 3423.64 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7630.96 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 61532.02 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 12.29 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सप्ताह के अंत में सोना के वायदाओं में 13255 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 46169 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 7499 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 121041 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 13249 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 12532 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 30751 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 74466 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 11849 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 22188 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सप्ताह के आरंभ में 31172 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 33407 के उच्च और 31000 के नीचले स्तर को छूकर, 1553 पॉइंट बढ़कर 32563 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

इंजीनियरिंग कार्य हेतु लिए गए ब्लॉक के

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा चुरू–आसलू–दूधवा खारा स्टेशनों के मध्य पैच डबलिंग कार्य एवं स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली के कमीशनिंग कार्य हेतु लिए गए ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल से होकर संचालित भावनगर–हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन को पूर्णतः निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में लिए गए डायवर्जन के निर्णय को निरस्त करते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं परिचालनिक कारणों से इस ट्रेन को पूर्णतः निरस्त किया गया है।

निरस्त की जाने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1.दिनांक 19.01.2026 एवं 22.01.2026 को भावनगर टर्मिनस से चलने वाली ट्रेन संख्या 19271 भावनगर–हरिद्वार एक्सप्रेस पूर्णतः निरस्त रहेगी।

2.दिनांक 21.01.2026 एवं 24.01.2026 को हरिद्वार से चलने वाली ट्रेन संख्या 19272 हरिद्वार–भावनगर एक्सप्रेस पूर्णतः निरस्त रहेगी।

यात्रियों की सुविधा हेतु आरक्षित यात्रियों को एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे तथा सूचना विभिन्न माध्यमों से प्रचारित की जा रही है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अद्यतन जानकारी के लिए NTES ऐप पर निगरानी रखें अथवा भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें । यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेल प्रशासन खेद प्रकट करता है।

पश्चिम रेलवे द्वारा कलोल स्टेशन पर चार ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव

(जीएनएस)। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की बहुप्रतीक्षित मांग को ध्यान में रखते हुए वलसाड–वडनगर एक्सप्रेस, जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर–साबरमती एक्सप्रेस और दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों का कलोल स्टेशन पर प्रायोगिक आधार पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों का कलोल स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान का समय निम्नानुसार रहेगाः

1. ट्रेन संख्या 20959/20960 वलसाड–वडनगर-वलसाड सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20959 वलसाड–वडनगर एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 11.37 बजे आगमन एवं 11.39 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 20960 वडनगर-वलसाड एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 18.15 बजे आगमन एवं 18.17 बजे प्रस्थान करेगी।

2. ट्रेन संख्या 12215/12216 दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12215 दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 22.41 बजे आगमन एवं 22.43 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 20.11 बजे आगमन एवं 20.13 बजे प्रस्थान करेगी।

3. ट्रेन संख्या 16507/16508 जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 16507 जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 12.55 बजे आगमन एवं 12.57 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 16508 केएसआर बेंगलुरु-जोधपुर एक्सप्रेस 17 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 06.19 बजे आगमन एवं 06.21 बजे प्रस्थान करेगी।

4. ट्रेन संख्या 15269/15270 मुजफ्फरपुर–साबरमती साप्ताहिक जनसाधारण एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 15269 मुजफ्फरपुर–साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस 20 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 05.53 बजे आगमन एवं 05.55 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस 20 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 18.28 बजे आगमन एवं 18.30 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।